



# भारत का गज़त पत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ल. 7]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1987/फाल्गुन 9, 1908

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1987/PHALGUNA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्य संघ प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा आरी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than Administrations of Union  
Territories)

## भारत रिपब्लिक आयोग

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1987

आदेश

आ. अ. 24:—1985 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन में 239-चकिया (प्र.जा.) निर्वाचन-शेत्र से निर्वाचन नहीं लड़ने वाले अध्यर्थी श्री मन्त्र प्रकाश सोमकर, श्री-36/22-A, ब्रह्मानन्द नगर कालोनी, द्वारा कुण्ड, (मंकट मोर्चन), वाराणसी को निर्वाचन आयोग द्वारा अपने नारीबा 10 जून, 1986 के आदेश संख्या 76/उ.प्र.—वि.स./85(4) के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्यायों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण उन पर अधिरोपित निरहृता हटाने की धारा 10-के अधीन, निरहृत किया गया था;

उक्त श्री मन्त्र प्रकाश सोमकर ने निर्वाचन आयोग के सक्षम एक अर्जी दाखिल की है जिसमें अपने निर्वाचन-व्यायों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण उनमें सुन् उन पर अधिरोपित निरहृता हटाने की प्रार्थना की है;

लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहने के लिए उक्त अर्जी में बताए गए कारण पर विवाद करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भत्त है कि उक्ति, नारीबा 10 जून, 1986 के आदेश के पुनरीक्षण की आवश्यकता है;

भत्त, यद्य प्रिवाक्षिन आयोग, उक्त अधिनियम की द्वारा 11 द्वारा प्रसरण शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मन्त्र प्रकाश सोमकर पर अधिरोपित निरहृता नारीबा 2 फरवरी, 1987 से हटाता है।

[सं. 76/उ.प्र.—वि.स./85]

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 2nd February, 1987

## ORDER

O.N. 24.—Whereas Shri Satya Prakash Sonkar, B36/22-A, Brahmanand Nagar Colony, Durga Kund, (Sankat Mochan) Varanasi, who was a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 1985 from 239-Chakia(SC) constituency, was disqualified by the Election Commission vide its Order No. 76/UP-LA/85(4) dated the 10th June, 1986 under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for the failure to lodge any account of his election expenses under the said Act and the rules made thereunder;

And whereas, the said Shri Satya Prakash Sonkar has submitted a petition before the Election Commission praying for the removal of the disqualification imposed on him giving reasons for his failure to lodge the account of election expenses;

And whereas, the Election Commission having taken into account the circumstances explained in the said petition for his failure to lodge the account is of the view that the earlier order of 10th June, 1986 merits revision;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission hereby removes the disqualification imposed on Shri Satya Prakash Sonkar with effect from 2nd February, 1987.

[No. 76/UP-LA/85]

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1987

आदेश

आ. प्र. 25.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1985 में हुए कानूनिक विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 186—शीर-हस्ती निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अध्यर्थी वी लक्ष्मी लालसिंह दक्षाया, केरेहस्ती टोडा, शीरहस्ती तानुरु, कलटिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा उसके अधीन बताए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का लेखा रीति में वाचिल करने में असम्भव रहा है;

उक्त अध्यर्थी ने सम्भक्ष सूचना दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए या तो कोई कारण अवश्यकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोचित्य नहीं है;

अतः यद्यपि निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में श्री लक्ष्मी लालसिंह दक्षाया को संसद के किसी भी सदन के

आ. प्र. 26.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिश्चित उप-निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिश्चित निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके मामले विनिश्चित निर्वाचन लड़ने वाला अध्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा उसके अधीन बताए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा उपचारित करने में अपने निर्वाचन व्यर्थों का लेखा समय के असर्गत और अपेक्षित रीति से वाचिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अध्यर्थियों ने सम्भक्ष सूचना दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए या तो कोई कारण अवश्यकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अध्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोचित्य नहीं है;

अतः यद्यपि निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम को धारा 10-के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिश्चित व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अवश्यक विधान परिषद् के सरकार और होमे के लिए आदेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम	निर्वाचन का विवरण	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अ. सं. और माम	निर्वाचन लड़ने वाले अध्यर्थी का नाम और पता	निर्वाचन लड़ने वाले अध्यर्थी का नाम और पता
1	2	3	4	5
272.	तमिलनाडु विधानसभा के लिए 204—अल्लूकोट्टू	उप-निर्वाचन	सर्वाधी जी. शुभुकुण्णन, पुत्र श्री गोपिनाथमी श्रापूर्णनी गाँड़न, न. 5, कार्ट ट्रैक रोड, त्यागराजा नगर, मद्रास-100017	निर्वाचनों व्यर्थों का लेखा समय के असर्गत और अपेक्षित रीति से वाचिल करने में असफल रहे।
273.	लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन 38—निलैन्तुरु	तमिलनाडु	पास. अलगुसुव्वरम, पुत्र श्री मामानाथन, 34, कोलाओयामारु कोरडनाडु मेलाटुरुगाड़, तमिलनाडु।	-वारी-

[म. 76/त. न. /86(272-273)]

आदेश से,  
मी. एन. रोज, सचिव

या किसी राज्य की विधान सभा अवश्यक विधान परिषद् के गवर्नर जी ने और होमे के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[मंज्ञा 76/कर्ना.-वि. म. /86/385]

New Delhi, the 9th February, 1987

## ORDER

O.N. 25.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Laxmi Lalsing Dakappa, Kerehalli Tands, Shirhatti taluk, Karnataka, a contesting candidate for the General Election to the Karnataka Legislative Assembly held in 1985 from 186. Shirhatti constituency has failed to lodge the account in the manner required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Laxmi Lalsing Dakappa to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76/KT-LA/86/385]

## ORDER

O.N. 26.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the bye-elections as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of his election expenses, within the time and in the manner as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished

any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order:—

## TABLE

Sl. No.	Particulars of election	S. No. and name of constituency	Name of candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
272.	Bye-election to the Tamil - Nadu Legislative Assembly	204.—Aruppukkottai	S/Shri G. Muthurkrishnan S/O Govindasamy, Annapoorani Garden, No. 5, Cart track Road, Thiyagaraya Nagar, Madras-600 017.	Account not lodged in time and in the manner.
273.	Bye-election to the House of the People-Tamil Nadu	38.—Tiruchendur	S. Alagusundaram, S/o Saminathan, 3A. Keelothasaraipu Koorainadu, Mailaduthurai, Tamil Nadu.	-do-

[No. 76/TN/86 (272-273)]

By Order,  
C. L. ROSE, Secy.

मई विल्सनी, 5 फरवरी, 1987

आ.म. 27.—नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन प्रायोग, नागार्लैंड सरकार के प्रतामर्श से श्री एन. जाक्कालू, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री टी.मी.के. लोठा, विकास आयुक्त को उनके कार्य भार संभासने की तारीख में अगले आवेशों तक नागार्लैंड राज्य के मुख्य निर्वाचन प्रधिकारी के रूप में एतत्प्रदारा नाम-निर्देशित करता है।

[सं. 154/नागार्लैंड/87]

आवेश से,  
आर. पी. भला, सचिव

[No. 154/NL/87]

By order,  
R. P. BHALLA, Secy.

मई विल्सनी, 8 फरवरी, 1987

संदेश

आ.म. 28.—निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की मारणी के स्तम्भ (2) में व्या विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा के सिए साधारण निर्वाचन, 1985 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अध्यक्ष, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा नद्दीन बनाए गए नियर्म द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में व्या उपर्याप्त रूप अपन निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और उक्त अध्ययियों ने सम्बद्ध सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया या उसके द्वारा तिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विवार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या त्यावैचित्र नहीं है;

इति: शब्द, निवाचित द्वारा दी गयी उक्त प्रधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में निर्वाचित व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की, विधान सभा प्रधान परिषद् के सदस्य बने जाने और होने के लिए इस ग्रांडेश की तारीख से तीन वर्ष की कासमयित्व के लिए निर्वाचित घोषित करता है;

नम्बर-	निवाचित की विधिविधा	निवाचित-क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निवाचित सदने वाले अध्यर्थी का नाम व पता	निराहूता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निवाचित, 1985	27—गोपेश्वरी (अ. जा.)	श्री श्रीम प्राकर्ण, मो. होलीवाला हिरनवाला, हसनपुर जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	निवाचित व्ययों का कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	—वही—	—वही—	श्री राजेन्द्र कुमार बाल्मीकि, मो. होज भवेसरा, सराय, तह. सम्मल, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	—वही—
3.	—वही—	29—बहौद	श्री मदन, प्राम बेटला, सम्मल, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	—वही—
4.	—वही—	—वही—	श्री सोम पाल सिंह, प्राम बुधपुर, सम्मल, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	—वही—
5.	—वही—	33—मुरादाबाद	श्री गोपाल दास, कट्टरा पूरब जाट, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	—वही—
6.	—वही—	—वही—	श्री राम प्रसाद, कट्टरवीब, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	—वही—
7.	—वही—	61—पुंछाया (अ. जा.)	श्री हरीनन्दन स्वरूप, टी. 2 ए. रेलवे कालोनी, शाहजाहानपुर (उत्तर प्रदेश)	निवाचित व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा रीति से दाखिल नहीं किया।
8.	—वही—	150—बलरामपुर	सतेश्वर प्रसाद, मो. मोती सागर, पोस्ट बलरामपुर (तुलसीपार्क), जिला गोपेश्वर (उत्तर प्रदेश)	निवाचित व्ययों का कोई लेखा दाखिल नहीं किया।
9.	—वही—	289—बिलहोर (अ. जा.)	श्री रामजीवन, प्राम बकहरदीली, पोस्ट मलावत जिला कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश)	—वही—

New Delhi, the 9th February, 1987

## ORDER

O.N. 28.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly, 1985 specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission or after considering the representations made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

## TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name and address of the Contesting Candidate	Reason of disqualification
			4	5
1.	General Election to the U.P. Legislative Assembly, 1985.	27—Gangeshwari (SC)	Shri Om Prakash, Moh. Holiwala Hiranwala, Hasanpur, Distt. Moradabad (U.P.)	Failed to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Rajinder Kumar Balmiki, Moh. Hoj Bhadesra Sarai, Teh. Sambhal, Distt. Moradabad (U.P.)	-do-
3.	-do-	29—Bahjoi	Shri Madan, Vill. Betla, Sambhal, Distt. Moradabad (U.P.)	-do-
4.	-do-	-do-	Shri Som Pal Singh, Vill. Dooghpur, Sambhal, Distt. Moradabad (U.P.)	-do-
5.	-do-	33—Moradabad	Shri Gopal Das, Katra Puran Jat, Distt. Moradabad (U.P.)	-do-
6.	-do-	-do-	Shri Ram Prasad, Katgharibch, Distt. Moradabad (U.P.)	-do-
7.	-do-	61—Powayan (SC)	Shri Hari Nandan Swaroop, T 2A Railway Colony, Shahjahanpur (U.P.)	Failed to lodge the account within the time and in the manner.
8.	-do-	156—Balrampur	Shri Satendra Prasad, Mohalla Moti Sagar, (Tulsi Park), Post Balrampur, Distt. Gonda (U.P.)	Failed to lodge any account of election expenses.
9.	-do-	299—Bilhaur (SC)	Shri Ram Jeevan, Vill. Chakhardauli, Post Majhawan, Distt. Kanpur Dehat (U.P.)	-do-

[No. 76/UP-LA/85 (12)]

## प्रावेश

आ. प्र. 29.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिविष्ट लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1984 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिविष्ट निर्वाचन-संकेत में हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिविष्ट निर्वाचन संकेत सारणी के स्तम्भ (5) में यथा उपर्युक्त रूप में अपने निर्वाचन व्यवस्था का लेखा वालिल करने में असफल रहे हैं;

अंत अध्ययनियमों से सम्बन्धित सूचना दिए जाने परं गैर उक्त प्रसफलता के लिए या सो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अध्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या स्थायी विचय नहीं है,

अतः अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिविष्ट व्यक्तियों को सदस्य के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष भी कालावधि के लिए निराहुत घोषित करता है।

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन की विधिष्ठियां	निर्वाचन-क्षेत्र की अम सं. तथा नाम	निर्वाचन लड़ने वाले प्रमुखों का नाम	निराहुत का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए माध्यारण निर्वाचन, 1984	6—अमरोहा	श्री राम कुमार कमल, मो. रामनीमी, चन्दौसी। जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	निर्वाचन व्यक्तियों का कोई लेखा दर्शन नहीं किया।
2.	-वही-	77—खुर्जा (अ.जा.)	श्री खजान, ग्राम मंडावरा, सिकंदराबाद, जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री विनोद कुमार, सराय धारी, जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	-वही-

[स. 76/उ.प्र.-लो. स./85(12)]

आदेश से,  
सुरज प्रकाश, अवर सचिव

## ORDER

O.N. 29.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General election to the Lok Sabha, 1984 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after

due notice of the Election Commission or after considering the representations made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

## TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	S. No. & Name of Constituency	Name and address of the Contesting Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 1984.	6—Amoroha	Shri Ram Kumar Kamal, Moh. Ram Nomi, Chandausi, Distt. Moraabdaab, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	72—Khurja (SC)	Shri Khajan, Vill. -Mandawara, Shikenderabad, Distt-Bulandshahr, Uttar Pradesh	-do-
3.	-do-	-do-	Shri Vinod Kumar, Sarai Dhari, Distt-Bulandshahr, Uttar Pradesh.	-do-

[No. 76/UP--HP/85 (12)]

By Order,  
SURAJ PARKASH, Under Secy.

मई दिसंबर, 9 करवरी, 1987

## भारत

का.आ. 30: —निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के सम्बन्ध (2) में यथा विनिर्दिष्ट आसाम विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो सम्बन्ध (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हूँगा है, सम्बन्ध (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अध्यवर्षी, तोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नया नहीं बनाए गए तियाँ द्वारा घोषित उन सारणी के सम्बन्ध (5) में यथा उपवर्शित स्पष्ट में अपने निर्वाचन व्यक्तियों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अध्यवर्षीयों ने सम्पूर्ण सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण घब्बा स्पष्टीकरण नहीं किया है या उसके द्वारा दिए गए अध्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः, घब्बा, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की घारा 10-के अनुमति में नीचे की सारणी के सम्बन्ध (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अधिकार विधान परिषद् के सदस्य बने जाने और होने के लिए भारत की तारीख से तीम वर्ष की कालावधि के निरूपित घोषित करता है।

## सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अध्यवर्षी का नाम और पता	निरहता का कारण
200.	आसाम विधान सभा के लिए समाधान निर्वाचन, 1985	89—कालियांड्रे	श्री नरेन्द्र चन्द्र घर्मन, ग्राम लालनवन्द्वा, डाकघाना अस्सागम, जिला नौगांव, आसाम	लेखा विधि द्वारा घोषित समय के असंगत और रीति से दाखिल नहीं किया गया।
201.	-वही-	97—देगांव (अ. जा.)	श्री बीरेन्द्र नाथ हुजारिका, बासुनी बैदान, लक्ष्मीनगर, यार्ड नं. 30, उप खंड, गोहाटी, जिला कामरुप, गोहाटी-781021	-वही-
202.	-वही-	105—महामाग	श्री शिरोद राज कंवर, माल मधुरापुर टी.ई., डाकघाना साल मधुरापुर, जिला सिबसागर (आसाम)	अपने निर्वाचन व्यक्तियों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
203.	-वही-	106—सोनारी	श्री अस्ताश हुसैन सोनारी टाउन, बाई नं. 3, डाकघाना सोनारी, जिला सिबसागर, आसाम	-वही-
204.	-वही-	106—सोनारी	श्री देव कूकन, टौबकाक टी.ई. डाकघर सोनारी, जिला सिबसागर, आसाम	-वही-
205.	-वही-	106—सोनारी	श्री गोपाल चन्द्र बाग, बोरहाट टी.ई., डाकघर बोरहाट, जिला सिबसागर, आसाम	लेखा विधि द्वारा घोषित रीति से दाखिल करने में असफल रहा।

[स. 76/आसाम/86]

New Delhi, the 9th February, 1987

## ORDER

O. N. 30:—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the election to the Legislative Assembly of Assam as specified in column (2) and hold from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation of the said failure even after due notice of the Election Commission; after considering the representations made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now therefore in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	No. and Name of constituency	Name of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
200.	General Election to the Legislative Assembly of Assam, 1985.	89—Kaliabor	Shri Narendra Chandra Barman Village Lakhanabandha P. O. Ambagoan District Nagaland Assam.	Account not lodged within the time and in the manner required by law.
201.	-do-	97—Dergaon (SC)	Shri Birendra Nath Hazarika Bamanimulian Lakhinagar Ward No. 30, Sub-Division Gauhati, District Kamrup, Gauhati-781021.	-do-
202.	-do-	105—Mahmara	Shri Kshirod Raj Konwar, Sarv Mathurapur T.E., P. O. Saru Mathurapur, District Sibsagar, Assam.	Failed to lodge any account of his election expenses.
203.	-do-	106—Sonari	Shri Alibah Hussain, Sonari Town Ward No. 3, P. O. Sonari, District Sibsagar, Assam.	-do-
204.	-do-	106—Sonari	Shri Deba Phukan, Towkak T.E., P. O. Sonari, District Sibsagar, Assam.	-do-
205.	-do-	106—Sonari	Shri Gopal Chandra Bagh, Borhat T.E., P. O. Borhat, District Sibsagar, Assam.	Failed to lodge the account in the manner required by law.

[No. 76/AS/86]

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1987

आदेश

आ.ब. 31:— निवासित आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की मार्गी के स्वरूप (2) में यथा विनिर्विष्ट बिहार विधान सभा के माध्यम से उप-विधायिका के लिए, जो स्वरूप (3) में विनिर्विष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्वरूप (4) में उसके सामने विनिर्विष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक ग्राम्यी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन चनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त मार्गी के स्वरूप (5) में यथा उपदर्शित रूप में आमने निवाचित व्यक्तियों का ऐसा समय के अन्तर्गत और/अथवा अनेक रीति से दायित रखने में असफल रहा है;

और उक्त ग्राम्यीयों में सम्पूर्ण सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या सो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अध्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निवासित आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पाण उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या स्पष्टीकरण नहीं है;—

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में नीचे की मार्गी के स्वरूप (4) में विनिर्विष्ट व्यक्तियों को समूद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/मध्य राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधास परिषद् के सदस्य चुने जाने और जाने के लिए आदेश का नारीख से तीन बर्ष की कालावधि के निरन्तर घोषित करता है।

## सारणी

क्रम संख्या	नियोजन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन-सील की क्रम संख्या और माम	नियोजन लाइने वाले द्वारा दर्शाएँ की गयी और पता	निरहूता का फोरें
1	2	3	4	5
1.	बिहार विधान के लिए उप-नियोजन 1985	11—किशनपुर	श्री विनोदानन्द मा, प्राम-पौ, बैनेनिया, जिला सहरसा, बिहार।	नियोजन स्थियों का लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	—वही—	—वही—	श्री शिव ना, मंडल, प्राम अंचलपुर, पौ, महादेवस्थान, जिला सहरसा, बिहार।	—वही—
3.	बिहार विधान सभा का साधारण नियोजन, 1985	165—पीरपेंटी	श्री अनश्व लाल मंडल, प्राम रामीपुर, पौ, लगमांहाट, कहुलगांव, भागलपुर, बिहार।	—वही—
4.	—वही—	—वही—	श्री राम लखन तांती, प्राम सुन्दरपुर, पौ.—पीरपेंटी, घाना—पीरपेंटी, भागलपुर, बिहार।	—वही—
5.	—वही—	166—कहुलगांव	श्री बाल मुकुम्ब माह, मो, चौधरी टोला, कहुलगांव, बिहार।	—वही—
6.	—वही—	166—कहुलगांव	श्री आसुवेप्रसाद सिंह, प्राम—पौ, मुरान, भागलपुर, बिहार।	—वही—
7.	—वही—	167—नाथनगर	श्री प्ररुण कुमार, प्राम बैरिया, पौ, शकरपुर चौषिनिया, भागलपुर, बिहार।	—वही—
8.	—वही—	—वही—	श्री पंचानन्द ठाकुर, प्राम उरपा, पौ, रूपसा, भागलपुर, बिहार।	—वही—
9.	—वही—	—वही—	श्री पटवारी मंडल, हवीषपुर, भागलपुर, बिहार।	—वही—
10.	—वही—	—वही—	श्री राजेश प्रा. मंडल, प्राम राधोपुर, पौ.—हरिहासपुर, नाथनगर, भागलपुर, बिहार।	—वही—
11.	—वही—	—वही—	श्री राम नरेण प्रसाद सिंह, बिरलीघ, घाना सज्जीर, मंडलपुर, बिहार।	—वही—
12.	—वही—	167—नाथनगर	श्री हृषीक उर्फ बैतू, प्राम बलुवालक, पौ, पुरेशी, भागलपुर, बिहार।	—वही—

1	2	3	4	5
13.	विहार विधान सभा के लिए साधारण नियोजन, 1985	168—भागलपुर	श्री उदय शंकर शर्मा, ग्राम कोईरी टोला, पो. हजौरपुर, बिहार।	निर्वाचन व्यवों का लेखा दाखिल गर्ती किया।
14.	—वही—	—वही—	श्री महाशीर लाल, ग्राम—पो. सबौर, भागलपुर, बिहार।	—वही—
15.	—वही—	—वही—	श्री राम मारामक साह, स्थान—पो. जगदीशपुर, भागलपुर, बिहार।	—वही—
16.	—वही—	169—गोपालपुर	श्री चिरंजीवी राम, ग्राम—पो. करारी तीनटंगा, धाना—गोपालपुर, जिला भागलपुर, बिहार।	—वही—
17.	—वही—	170—बिहुर	श्री बेदा नन्द कुबर, ग्राम व पो. सोनबरसा, पो. एस. बिहुर, जिला भागलपुर, बिहार।	—वही—
18.	—वही—	170—बिहुर	पो. उमा कान्त शर्मा, ग्राम द्रमरपुर, पो. भावानगामा, पी.एस. बिहुर, जिला भागलपुर, बिहार।	—वही—
19.	—वही—	171—सुल्तानगंज (प्र.भा.)	श्री गोदवीन रघुनं, ग्राम व पो. सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार।	—वही—
20.	—वही—	—वही—	श्री लक्ष्मीकाल माई, ग्राम सादपुर, पो. पचलकी बाजार, भागलपुर, बिहार।	—वही—
21.	—वही—	172—झमरपुर	श्री प्रकाश कुमार यादव, ग्राम रामपुर, पत्तालय कठैल, जिला भागलपुर, बिहार।	—वही—
22.	—वही—	174—बोका	श्री स्तोताराम सिंह, ग्राम बिहुडी, (भयहाट, पालक), भागलपुर, बिहार।	—वही—
23.	—वही—	175—बेलहर	श्री नियामुल मिया, ग्राम घोड़पड़ा, पत्तालय—बसमता, जिला भागलपुर, बिहार।	—वही—
24.	—वही—	—वही—	श्री राम देव शर्मा, ग्राम खोसर, पत्तालय खोसर, जिला भागलपुर, बिहार।	—वही—

1	2	3	4	5
25. — <del>वही</del> —	— <del>वही</del> —	वी सत्येन पंचित, पाम बारा उम्मी, प्राप्ताय बारा, जिला भागलपुर, बिहार।	— <del>वही</del> —	

[पं. ७६/बिहार—वि. स./८५]  
ए. डॉ. प्रदीप, अवर सचिव

### ORDER

O. N. 31 :—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the election to the Bihar Legislative Assembly Bye-elections as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses or failed to lodge the account within the time and or in the manner, as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representations made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this order.

### TABLE

Sl. No.	Particulars of election	S. No. and Name of the Parliamentary/Assembly Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-elections to Bihar Legislative Assembly-1985	111—Kishanpur	Shri Venodanand Jha, Vill - P.O. Banainia, Dist. Saharsa, Bihar.	Account of election expenses not lodged.
2.	-do-	-do-	Shri Shiv Narain Mondal, Vill. Achalpur, P. O. Mahadeo Asthan, Dist. Saharsa, Bihar.	-do-
3.	General Elections to Bihar Legislative Assembly, 1985	165—Pirpantry	Shri Anant Lal Mandal, Vill. Ranipur, P. O. Lagmihat, Colganj, Bhagalpur, Bihar.	-do-
4.	-do-	-do-	Shri Ram Lakhman Tanti, Vill. Sunderpur, P. O. Pirpatti, Bhagalpur, Bihar.	-do-
5.	-do-	166—Kahalgaon	Shri Bal Mukund Sah, At-Cheudharitola, Kahalgaon, Bihar.	-do-
6.	-do-	-do-	Shri Basudeo Pd. Sah, At-P.O. Murhan, Bhagalpur (Bihar).	-do-
7.	-do-	167—Nathnagar	Shri Arun Kumar, Vill. Baria, P. O. Shankarpur, Bhagalpur (Bihar).	-do-

1	2	3	4	5
8.	General Elections to Bihar Legislative Assembly-1985	157—Nathnagar	Shri Panchanand Thakur, Vill. Darpa, P. O. Rupsa, Bhagalpur (Bihar)	Account of election expenses not lodged.
9.	-do-	-do-	Shri Patwari Mandal, Habibpur, Bhagalpur	-do-
10.	-do-	-do-	Shri Rajendra Prasad Mandol, Vill. Raghopur, P. O. Haridaspur, Bhagalpur (Bihar)	-do-
11.	-do-	-do-	Shri Ram Naresh Pd. Singh, Birnodh, Sabono, Bhagalpur (Bihar)	-do-
12.	-do-	-do-	Shri Halim Alias Ka-ilu, Vill. Baluachak, P. O. Puraini, Bhagalpur (Bihar)	-do-
13.	-do-	168—Bhagalpur	Shri Udai Shankar Verma, Vill. Koeri Tola, P. O. Habibpur, Bhagalpur (Bihar)	-do-
14.	-do-	-do-	Shri Mahabir Lal, Vill. P. O. Sabour, Bhagalpur, Bihar.	-do-
15.	-do-	-do-	Shri Ram Narain Sah, Vill-P.O. Jadishpur, Bhagalpur (Bihar)	-do-
16.	-do-	169—Gopalpur	Shri Chiranjibl Ral, Vill-P. O. Karari, Taitanga, Bhagalpur (Bihar)	-do-
17.	-do-	170—Bihpur	Shri Bedanand Kumar, Vill-P. O. Sonbarsa, P. S. Bihpur, Dist. Bhagalpur (Bihar)	-do-
18.	-do-	-do-	Prof. Uma Kant Sharma, Vill. Amarpur, P. O. Babhangama, P. S. Bihpur, Dist. Bhagalpur, Bihar.	-do-
19.	-do-	171—Sultanganj (SC)	Shri Goverdhan Rajak, Vill. Purani Durga, Asthan, Sultanganj, P. S. Sultanganj, Bhagalpur (Bihar)	-do-
20.	-do-	-do-	Shri Laxmi Kant Manjhi, Vill. Sadhpur, P. O. Pachrukhi Bazar, Bhagalpur (Bihar)	-do-
21.	-do-	172—Amarpur	Shri Prakash Kumar Yadav Vill. Rampur, P. O. Kathel, Dist. Bhagalpur (Bihar)	-do-

1	2	3	4	5
22.	General Elections to Bihar Legislative Assembly-1985.	174—Banka	Shri Sita Ram Singh, Vill. Khiddi, P. O. Vijayhat, Dist. Bhagalpur (Bihar)	Account of election expenses not lodged.
23.	-do-	175—Belhar	Shri Nivamull Mian, Vill. Ghosmara, P. O. Basmata, Bhagalpur (Bihar)	-do-
24.	-do-	-do-	Shri Ramdeo Sharma, Vill-P. O. Kheser, Bhagalpur (Bihar)	-do-
25.	-do-	-do-	Shri Sahdeo Pandit, Vill- Basaulhi, P. O. Bara, Bhagalpur (Bihar)	-do-

[No. 76/BR-LA (85)]

S.D. PERSHAD, Undr Secy.

पर्याली, 16 फरवरी, 1987

पा.प्र. 32.—1984 की निर्वाचन अर्जी सं. 1/1 में गोपाली उच्च न्यायालय, इन्फाल थंक, के तारीख 24-1-1987 के तिरंगे और भारत को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा प्रकाशित करता है।

[सं. 82/मरि. 1/1/84]

आदेश द्वा

एम.आर. प्रशाद, अवर मंत्री

New Delhi, the 16th February, 1987

O.N. 32.—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the judgement and Order dated 24-1-87 of the Gauhati High Court, Imphal Bench, in Election Petition No. 1/1 of 1984.

[No. 82/MR/1/1/84]

By Order,

S. D. PERSHAD, Under Secy.

## IN THE GUAHATI HIGH COURT

(HIGH COURT OF ASSAM, NAGALAND,  
MEGHALAYA, MANIPUR & TRIPURA)  
IMPHAL BENCH

By Notification No. 318/84(1B) dated 12-3-84  
The Election Commission of India called upon the Members  
of the Election Petition No. 1/1 of 1984

Thokhom Achouba Singh .. Petitioner.

v.

Rajkumar Jaichandra Singh  
and Ors. .. Respondents

## PRESENT :

The Hon'ble Justice T. C. Das

For the Petitioner—Mr. C. Komal Singh, Mr. K. Kumar Singh and Mr. A. Chaoba Singh, Advocates.

For the Respondents—Mr. Th. Priyananda Singh Mr. R. K. Saratchandra Sinha, Mr. S. Lakhikanta Singh and Mr. B. K. Sarma, Advocates.

## Date of Judgment and Order :

## JUDGMENT &amp; ORDER

By Notification No 318/84(1B) dated 12-3-84 the Election Commission of India called upon the Members of the Manipur Legislative Assembly to elect one member to the

Council of States. Accordingly 19th day of March, 1984 was notified as the last date for submission of nomination, 20th March, 1984 for the scrutiny of nomination, 22nd March, 1984 as the last date for withdrawal of the candidature, 29th March, 1984 as the date of poll and 31st March, 1984 as the date before which the whole process of election was to be completed. In consultation with the Government of Manipur, the respondent No. 4 was appointed by the Election Commission of India as Returning Officer for the said election. By a notification, the Election Commission also designated the Deputy Secretary, Manipur Legislative Assembly as the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer, respondent No. 4. The relevant notification was accordingly published in the Manipur Gazette on March 12, 1984 by the Chief Election Officer, Manipur. By notification No. 1/29/84-(Per) dated 12-3-84, the Returning Officer notified that the nomination papers may be delivered to the Returning Officer or to the Assistant Returning Officer at the Assembly Secretariate, Imphal between 11 A.M. and 3 P.M. on any date other than a public holiday and not later than 19th March, 1984.

2. It is stated by the election petitioner in his petition that the Government of Manipur in exercise of the powers conferred by explanation to Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1981 read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. 21/18/72-Judl. dated 27-4-72, published the lists of holidays for general information through gazette notification dated 14-12-83 annexed as Appendix-I and Appendix-II declaring general holidays and also public holidays for the calendar year, 1984. According to the petitioner, 19th March, 1984 was declared as General Holiday as per Appendix-I as well as a Public Holiday as per Appendix-II of the said notification (Ext. P/1). But the respondent Nos. 1, 2 and 3 submitted their nominations on 19th March, 84. The petitioner, however, submitted his nomination on 16-3-84 to the Returning Officer who accepted the same without objection. The petitioner in his petition has further stated that 19-3-84 which was the last date for submission of nomination papers was General Holiday as well as a Public Holiday and as such no nomination papers could have been presented by respondent Nos. 1, 2 and 3 either on 19-3-84 or on 20-3-84. It is stated by the petitioner that the acceptance of nomination papers of Respondent Nos. 1, 2 and 3 by respondent No. 4, (the Returning Officer) is contrary to and against the provisions of the Proviso to sub-section (1) of Section 33 of the Representation of the People Act, 1951 (for short, 'the R. P. Act'). On 20-3-84 the nomination papers were taken up for scrutiny by the Returning Officer and on the said date the proposer of the petitioner raised objection for acceptance of nomination papers of respondent nos. 1, 2 and 3 and pleaded for rejection of those nomination papers having filed contrary to the mandatory provisions of Section 33 of the R. P. Act. It is further stated by the petitioner that the Returning Officer, respondent no. 4 turned down the objection and illegally accepted the nomination

papers of respondent Nos. 1, 2 and 3. The respondent No. 3, however, withdrew from his candidature and as such the Returning Officer published the names of the petitioners and Respondent Nos. 1 and 2 to be contesting candidates for the said election as required by Rule 11 of the Conduct of Election Rules, 1961 (hereinafter called 'the Rules'). After poll was held on 29-3-84, the Returning Officer declared respondent No. 1 as duly elected to fill up the seat in the Council of States as he obtained the majority of votes polled in this behalf. The petitioner being aggrieved by the said declaration of the result and declaring the respondent No. 1 to be duly elected as a member of Council of States, has challenged the result in his election petition. The petitioner has prayed that the result declaring respondent No. 1 as duly elected as member of Council of States may be declared invalid due to improper acceptance of the nomination papers of respondent Nos. 1 and 2 and the petitioner should be declared elected as a member of the Council of States as an uncontested candidate.

3. The respondent Nos. 1 and 4 filed their separate written statements and contested the election petition while denying the contentions raised by the petitioner, the respondents contended that the Government of Manipur by issuing a notification on 16-3-84, modified the list of general holidays published earlier with respect to 19-3-84 which was declared as a general holiday as per earlier notification. By the said notification dated 16-3-84, the Government of Manipur declared 20th March, 1984 as a general holiday instead of 19-3-84. It has been denied by the respondent No. 4 that the nomination papers were submitted by respondent Nos. 1, 2 and 3 on the day which was declared as a general holiday and that their nomination papers were improperly accepted. It has been further pleaded that the dates as regards filing of nomination papers, scrutiny, withdrawal of nomination papers, the date of poll and the date of completion of the election were all notified by the Election Commission of India and no such date as notified fell on public holidays and there cannot be any question of improper acceptance of nomination papers of Respondent Nos. 1, 2 and 3 by Respondent No. 4. It has been pleaded by respondent No. 1 that he having received maximum number of votes in his favour, he was declared elected. The respondents have prayed for dismissal of the election petition. On this aforesaid ground as raised by the election petitioner in this election voluntary petition and on the basis of the pleadings of the parties, the following issues were struck.

1. Whether 19-3-84 was a "public holiday" within the meaning of the proviso to sub-section (1) of Section 33 of the Representation of the People Act, 1951?
2. Whether the nomination papers of respondents 1, 2 and 3 were improperly accepted by respondent No. 4?
3. Whether the election of respondent No. 1 has been materially affected as a result of "improper acceptance" of the nomination paper?
4. To what relief is the election petitioner entitled?

The petitioner has examined himself and two other witnesses in support of his contention. From the analysis of above issues it appears that the only contest as raised by the petitioner in this election petition boils down to a single point for consideration as to whether 19-3-84 was declared as a "holiday" and the nomination papers of respondent Nos. 1, 2 & 3 were improperly accepted which has materially affected the result of the election.

After closure of the evidence and on hearing the learned counsel of the parties the issues were referred to the following effect :

- (1) whether 19-3-84 was a "general holiday" within the meaning of the proviso to sub-section (1) of section 33 of the Representation of the People Act, 1951 and whether the "general holiday" was treated as a "public holiday" within the meaning of the said provisions of the R. P. Act?

- (2) whether nomination papers of respondent Nos. 1, 2 & 3 were improperly accepted by respondent No. 4?
- (3) whether the result of the election of the petitioner has been materially affected as a result of the improper acceptance of nomination papers of respondent Nos. 1 and 2.
- (4) To what relief the election petitioner is entitled to?

5. Before taking up the issues in the light of the evidence on record it would be appropriate to refer to relevant annexures which are annexed to the petition of the election petitioner. Annexure-I is the notification issued from the Manipur Legislative Assembly Secretariat under notification No. 1/2(9)84/LA(Par) dated 12th March, 1984. The said notification invited the nomination papers of the intended candidate to contest the election of member to the Council of States by the elected members of the Manipur Legislative Assembly. It was further informed that the nomination papers might be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer or is the Deputy Secretary, Manipur Legislative Assembly, Assistant Returning Officer at the Assembly Secretariat Imphal between 11 A.M. on any day (other than public holiday) not later than 19th March, 1984. The date of scrutiny was fixed on 20-3-84 at 11 A.M. and the date of withdrawal was fixed on 22-3-84 whereas the date of poll was fixed on 29-3-84 between 10 A.M. and 2 P.M. in the Committee Room of the Manipur Legislative Assembly, Imphal. Expt. 91 is the order notification dated 21-11-83 issued by the Government of Manipur publishing the list of the general holiday for the state for the year 1984 vide Appendix-I of the said order and in exercise of the power conferred by the explanation to Section 25 of the Negotiable Instrument Act, 1891 read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. 21-18-72-Judl. dated 27-4-72 the Government of Manipur declared the list of public holidays for the year 1984 as specified in Appendix-II of the said order. On perusal of Exhibit P1 it appears that the list of holidays for the year 1984 was published by the Government of Manipur under two categories. One being list of "general holidays" and the other list of "public holidays" which was issued separately in exercise of the powers conferred by explanation to Section 25 of the N.I. Act. In Appendix-I which contained the general holidays' list, it appears that 19th March, 1984 was declared as general holiday on account of Doljatra (Yaosang). Annexure-A3 to the petition relates to another order/notification of the Government of Manipur, Imphal dated 16th March, 1984. The said order runs as follows :

"In partial modification of this Department order of even number dated 21-11-83, the Government of Manipur is pleased to declare that the 19th March, 1984 29 Phalguna 17 Lamda, Monday appearing at Sl. No. 3 of the Appendix-I thereto shall not be a General Holiday.

2. The Governor of Manipur is further pleased to declare 20th March, 1984 30 Phalguna 18 Lamda, Tuesday as General Holiday in place of 19th March, 1984 29 Phalguna 17 Lamda, Monday."

6. Annexure-A4 is the impugned order of the Returning Officer Manipur dated 20th March, 1984. The said order related to the acceptance of all the four nomination papers as valid. Annexure-A5 to the petition is the declaration of the election result by the Returning Officer on 29th March, 1984 declaring the respondent No. 1 Shri Rajkumar Jai-chandra Singh to be duly elected member to the Council of States for the Legislative Assembly, Manipur.

7. It is well known that an election dispute is not like an ordinary list between private parties. A free and fair election based on Universal Adult Franchise is the basic, the regulatory procedure for the function and distribution of Legislative, executive and judicative roles in the total scheme directed towards holding of free election. The courts while adjudicating upon election controversies must come to the conclusion that the result of the election was materially affected on any of the grounds as narrated in the Representation of the People Act.

8. Mr. Komol Singh, learned Counsel for the election petitioner has submitted that Issue No. 1 if decided would cover Issue No. 2 and 3 and in the alternative, issue No. 1 is the decisive factor to cover Issue Nos. 2 and 3. Referring to the list of 'Public Holiday' the learned counsel has submitted that the Central Government alone has the authority under Section 25 of the N.I. Act to declare the list of Public Holidays. Therefore, declaration of public holiday by the State Government is subject to delegation of power or authorisation by the Central Government. According to the learned counsel, public holiday already declared could not be changed by the State Government without any authority obtained from the Central Government or without any such delegation of power or authorisation by the Central Government. Referring to Appendix-II of Ext. P/1 the learned counsel has submitted that for publishing this notification relating to public holiday, the State Government was authorised by the Central Government to publish the list of public holidays. But the State Government could not change the list of public holidays as no such authorisation from the Central Government was obtained. Referring to Appendix-V of Exhibit P/1, the learned Counsel has submitted that there was insertion of words "Banks only" but in Appendix-I it was not so and there should be harmonious reading of Appendix-I and Appendix-II. Referring to Annexure-R/1 the learned counsel has submitted that there is no mention of "public holiday" in Annexure-R/1. Annexure-R/1 is meant only for administrative offices at Delhi and New Delhi during 1984. The contention of the learned counsel for the election petitioner is that the Election Commission was bound to follow the list of holidays as per Annexure R/1. The Election Commission of Manipur can only follow the procedure and rules and if there was illegal acceptance of nomination papers, those can not be accepted as valid. Hence, the petitioner should be declared as duly elected under Section 53(2) of the R. P. Act.

9. In reply, Mr. Th. Priyananda Singh, learned counsel for the respondent has submitted that burden lies on the petitioner to show that 19-3-84 was a public holiday. The Election Commission which was appointed by the Election Commission of India, New Delhi should follow the list of holidays published by Central Government. It is further submitted by the learned counsel that 19-3-84 was not a "public holiday" but was declared as a "general holiday" for the State of Manipur which was subsequently shifted to next day by another notification. In case of "General Holiday" the Government of Manipur has the power to revoke the earlier order and to shift the General Holiday under Section 21 of the General Clauses Act as per need of the public. But the state has no power to declare a list of public holiday under N.I. Act as no power can be delegated to them but to follow instruction of the Central Government. But in case of declaration of general holiday, the State Government may declare a General or Restricted holiday as per need of the public.

10. According to the learned counsel for the respondent, 19-3-84 was declared as a general holiday and the same not being a public holiday, the date could be changed according to the need of the people and as such it was shifted to 20-3-84 by subsequent notification.

11. From the above trend of the argument as advanced by the learned counsel of both the parties, it appears that the real controversy in this election petition is relating to the "public holiday" and "General Holiday" as incorporated in Issue No. 1. Before travelling to consider the contention of the learned counsel of the parties relating to the point at issue, let me take up the relevant provisions of the Representation of the People Act, 1951. Section 33(1) of the Act runs as follows :

"33. Presentation of nomination paper and requirements for a valid nomination.—(1) On or before the date appointed under clause (a) of section 30 each candidate shall, either in person or by his proposer, between the hours of eleven O'clock in the forenoon and three O'clock in the afternoon deliver to the returning officer at the place specified in this behalf in the notice issued under section 31 a nomination paper completed in the prescribed form and signed

by the candidate and by an elector of the constituency as proposer.

[Provided that no nomination paper shall be delivered to the returning officer on a day which is a public holiday]

Section 2(h) defines the Public Holiday :

"Public Holiday" means any day which is a public holiday for the purposes of Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881)."

The term 'General Holiday' has not been defined in the Act. Therefore, it is clear that the Act only describes the meaning of Public Holiday which is declared by the competent Government under the provisions of Section 25 of the N.I. Act. The other category of holiday which is known as General Holiday does not come within the purview of section 25 of the N.I. Act. List of Public Holidays as it reveals from the notification vide exhibit P/1 containing Appendix-II, was published in exercise of the powers conferred by explanation to Section 25 of the N.I. Act. It includes also the Bank Holidays. The list of general holidays and restricted holidays are published by the State Government according to the public need to observe holidays by the public or by a section of the society according to their need, social customs and traditions followed from time immemorial. Therefore, the list of general holidays for the public in a particular state or for a section of people of that state notified earlier can be changed as per prevailing circumstances and the need. The list of general holidays as also can be altered on the basis of the public festival which are usually done by the State Government according to the need of the people to observe a particular festival. But in case of the list of "public holidays" as published in exercise of the powers conferred by the explanation to Section 25 of the N.I. Act is entirely different from that of the list of general holidays published by the State Government.

12. Let me now take up Issue Nos. 1 & 2 together which are inter-connected.

Issue Nos. 1 & 2 :

The evidence of the petitioner's witnesses are mostly on the basis of the documents produced by the petitioner in the case. Therefore, the evidence of witnesses are also considered in the light of the document on record relating to the point at issue.

It is an admitted fact that by earlier notification dated 21st November, 1983, the list of general holidays was published by the Government of Manipur which shows that 19th March, 1984 was declared as general holiday for the state due to Doliatra. However, subsequently by order dated 16th March, 1984, the notification of the general holidays published on 21-11-83 was modified in respect of holiday on 19th March, 1984 and the holiday was altered from 19th March, 1984 to 20th March, 1984. This fact is clear from Annexure A/3 to the petition. As observed earlier, the State Government can change the list of holidays according to public need. It was felt by the Government that the actual observance of holiday ought to have been on 20th March, 1984 instead of 19th March, 1984 according to the public need and in that view of the matter the partial modification was made to alter the holiday from 19th March, 1984 to 20th March, 1984 by the subsequent notification and/or order dated 16th March, 1984. If that be the position, 19th March, 1984 was not a general holiday as submitted by the learned counsel for the respondent No. 1. Admittedly the nomination paper of the respondent No. 1 Rajkumar Lachandra Singh was filed on 19-3-84 on which date nomination papers of respondent Nos. 2 and 3 were also submitted to the Returning Officer. But the nomination paper of the election petitioner was filed on 16-3-84. On 20-3-84 Shri Ph. Parijat Singh who was the proposer of the petitioner submitted a petition to the Returning Officer stating that the nomination papers of respondent Nos. 1, 2 and 3 should be rejected as they were filed on 19-3-84 which was a public holiday. At the time of scrutiny of the nomination paper the Returning Officer considered the petition, heard the learned counsel of Ph. Parijat Singh but found that as the Government of Manipur subsequently declared 20th March, 1984 as "general" holiday instead of 19th

March, 1984, the submission of all the nomination papers on 19th March, 1984 were valid as the same did not contravene the provisions of Section 33 of the R.P. Act. The Returning Officer also found that the Government offices in the State of Manipur observed holiday on 20th March, 1984 instead of 19th March, 1984 as 'general holiday' and as such the candidates were entitled to submit their nomination papers on 19th March, 1984. The learned Returning Officer also observed that even if 19th March, 1984 was declared as a general holiday by virtue of earlier notification, the Returning Officer was not bound to follow the holiday list of the Government of Manipur as the office of the Returning Officer was functioning under the Election Commission of India which is bound to follow the list of "public holidays" issued by the Government of India. The learned Returning Officer, therefore, accepted all the nomination papers on the ground that they were all validly submitted nominations without any contravention of the provisions of law as laid down under Section 33(1) of the R.P. Act. Though the learned counsel for the petitioner has laid much stress on both the lists of holidays as contained in Appendix-I and Appendix-II of the notification published on 21st November, 1983, it would not be possible to ignore the subsequent notification issued by the Government of Manipur on 16th March, 1984 whereby the date of holiday was altered from 19th March to 20th March, 1984 to be observed by the public of Manipur as "general holiday" on account of Doljatra. It is, therefore, seen that the general holidays and public holidays are of distinct character and are different from each other. The Returning Office was therefore, correct in holding that all the nomination

papers of respondent Nos. 1, 2 and 3 were valid. Therefore, it appears that the submission of nomination papers of respondent Nos. 1, 2 and 3 on 19th March, 1984 did not contravene the provisions of Section 33(1) of the R.P. Act and they were properly accepted by respondent No. 4. The issue Nos. 1 and 2 are accordingly decided against the election petitioner.

Issue No. 3:

The decision on issue Nos. 1 and 2 above are sufficient to hold that the result of election has not been materially affected due to acceptance of nomination papers of respondent Nos. 1, 2 and 3. Moreover, the election petitioner has not been able to show by any material evidence either oral or documentary that the result of the election of the petitioner has been materially affected and unless it is shown by the petitioner that in fact, the result of the election has materially affected the petitioner, the petitioner cannot get any relief in this petition. Therefore, issue No. 3 is also decided against the petitioner.

Issue No. 4:

In view of the decision of the aforesaid issue against the petitioner, he is not entitled to any relief in this election petition. The petition is, therefore, dismissed with a nominal cost of Rs. 300. The petitioner shall pay the amount of Rs. 300 to respondent No. 1 which may be adjusted from his security deposit.

(Sd/-) T. C. DAS, Judge